एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 01 (जनवरी-फरवरी, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

कृषि बजट (2023-24): एक नज़र

(*सूर्य सिंह राजपुरोहित)
सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
*संवादी लेखक का ईमेल पता: suryasingh7861087@gmail.com

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। इस बार सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की गई है। कृषि स्टार्टअप के लिए एक डिजिटल एक्सेलेरेटर फंड बनाया जाएगा, जिसे कृषि निधि नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। बागवानी उत्पादों के लिए 2,200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा ही साथ ही खेती में आधुनिक तकनीक को भी बढ़ाया जाएगा। छोटे किसानों के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना का आवंटन 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया हैं। सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए बैंकों से लोन लेने में आसानी होगी। बजट पेश होने से पहले ही कहा जा रहा था कि इस बार सरकार ग्रामीण विकास पर फोकस करने जा रही है और यह खबर किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। इसमें देश से जुड़े करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलता है और हर साल छह हजार रुपये तीन किस्तों के रूप में हस्तांतरित किए जाते हैं। 13वीं किस्त जल्द ही आ रही है। पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में पैसे का भुगतान किया जाता है। इस तरह लाभार्थियों के खाते में अब तक इस योजना की 12 किस्तें जमा हो चुकी हैं। इसके तहत किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये आने की संभावना है। इसे फरवरी के पहले हफ्ते में क्रेडिट किया जा सकता है, इस तरह पीएम किसान स्कीम के तहत 13वीं इंस्टालमेंट ले सकते हैं, 13वीं इंस्टालमेंट लेने के लिए कुछ जरूरी नियम करने जरूरी हैं। इसके तहत सबसे पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। किसान बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए अपने निकटतम सीएससी केंद्रों तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद पीएम किसान वेबसाइट पर अपना आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड और पीएम किसान अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा। ओटीपी आने के बाद केवाईसी पूरी हो जाएगी।

वित्त मंत्री ने कई नई योजनाएं शुरू करने की बात भी कही है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की गई है। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं? 'इस बजट में सप्तऋषि की तरह सात प्राथमिकताएं हैं. पहला है समावेशी विकास। यह विकास किसानों, महिलाओं, ओबीसी, एससी-एसटी, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचना चाहिए। वंचितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर का भी ध्यान रखा गया है। इस प्राथमिकता के तहत, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इससे किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा, ऋण, बाजार खुफिया, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उत्पादन क्षमता और लाभ कमाने की क्षमता भी

बढ़ेगी। किसानों, सरकार और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ेगा। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। इससे आधुनिक तकनीक में भी इजाफा होगा।

आगे मोटे अनाज को लेकर भी एलान किए। 'मोटे अनाज जिसे श्री अन्न भी कहते हैं, इसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हम दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। छोटे किसानों ने नागरिकों की सेहत को मजबूत करने के लिए श्री अन्न उगाया है और बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार कपास की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देगी। इससे किसानों, सरकार और उद्योगों को साथ लाने में मदद मिलेगी।

1. 20 लाख क्रेडिट कार्ड: केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा।

2. किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल तरीके से किसानों की जाएगी मदद :- किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। यहां से किसानों को खेती संबंधित प्लानिंग, लोन, इंश्योरेंस और फसलों के उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही किसान इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से बाजार में अपनी फसल को अच्छी कीमत पर कैसे बेच पाएं, उसके बारे में भी उन्हें यहां से सहायता मिलेगी।

3. एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा खेती किसानी से संबंधित स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा: - केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। भारत सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बेहतर फंड मुहैया कराएगी। सरकार ग्रामीण इलाकों के नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करेगी। सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो फंड देगी उसकी मदद से किसानों की रोजमर्रा की समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। इस फंड की मदद से एग्री टेक-इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

4. मोटे अनाज को बढ़ावा भारत बनेगा ग्लोबल हब फॉर मिलेट: - सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना नाम दिया गया है। इसके जरिए देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मिलेट का एक्सपोर्टर है हम कई तरह के 'श्री अन्न का उत्पादन करते हैं इनमें ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनि, कुटकी, कोडो, छीना और सामा है। यह सभी मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। किसान लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में श्री अन्न का उत्पादन करके मदद कर रहे हैं। भारत को श्री अन्न के मामले में ग्लोबल हब बनाने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। यह संस्थान इंटरनेशनल लेवल पर मिलेट्स से संबंधित रिसर्च टेक्नोलॉजी और इसके बेहतर उत्पादन के तरीकों को बताता रहा है।

5. बागवानी के लिए क्या? सरकार ने इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है।

6. मछली पालन को भी मिलेगा बढ़ावा :- केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट

कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ावा देना है। मछली पालन और मछली बेचने का काम करने वाले छोटे-छोटे व्यापारियों की मदद के लिए उपयोग होगा। भारत सरकार मछली पालन के क्षेत्र को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करना चाहती है।

7. सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है; इनके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी, इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी।

8. प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा मदद: सरकार, अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यूनियन बजट 2023 में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए काफी कुछ खास रहा । ग्रीन एग्रीकल्चर, मिलेट, एग्री क्रेडिट, डिजिटल तकनीक से खेती, पशुपालन, मछली पालन, सहकार से समृद्धि, आदि पर सरकार का फोकस रहा । साल 2023 के बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। किसान समृद्धि योजना के बाद इस साल सरकार ने कई अन्य योजनाएं चालू करने की घोषणा की है। सरकार ने पशुपालकों और मछलीपालन करने वाले किसानों के लिए भी कई कदम उठाए हैं।

9. कॉटन की फसल पर ज्यादा ध्यान देगी सरकार: - बजट 2023 में कॉटन की फसल पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. सरकार ने कहा है कि वह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तैयार करेगी, जिसकी मदद से इसके उत्पादन और व्यापार में किसानों को मुनाफा होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है कि यह एक तरह का संबंध होगा जो किसान, राज्य सरकार और इंडस्ट्री के बीच स्थापित होगा।

10. क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़ रुपए: - क्लीन प्लांट प्रोग्राम का मतलब खेतों में ऐसी फसल लगाई जाए जो रोग मुक्त हो और जिनके पौधों से हाई वैल्यू वाले क्वालिटी अनाज का उत्पादन हो।

11. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा: - नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह काम आने वाले 3 सालों में किया जाएगा । वहीं 10000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे प्राकृतिक खेती के लिए माइक्रो फर्टिलाइजर पर जोर दिया जाएगा और इसके साथ ही मैन ग्रोन प्लांटेशन पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।